Drishti IAS

करेंट अफेयर्स मध्य प्रदेश

फरवरी 2024

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

मध्य प्रदेश **3**

- ‘एग्जाम पेपर लीक’ को रोकने हेतु कानून 3
- रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तथा पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना 3
- पीएम ने मध्य प्रदेश में परियोजनाओं का उद्घाटन किया 4
- सिंगरौली में हल्का भूकंप आया 5
- मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने पहला राज्य बजट पेश किया 6
- खजुराहो नृत्य महोत्सव के 50 वर्ष पूरे 6
- मध्य प्रदेश ने 'बैग लेस स्कूल' पहल शुरू की 8
- मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड को 'सर्वश्रेष्ठ राज्य पर्यटन बोर्ड' का पुरस्कार मिला 8
- प्रधानमंत्री ने रेलवे परियोजनाओं का अनावरण किया 9
- प्रधानमंत्री 'विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश' कार्यक्रम को संबोधित करेंगे 10
- मध्य प्रदेश भगवान कृष्ण से जुड़े स्थलों का विकास करेगा 10
- CAG ने मध्य प्रदेश पीएम आवास योजना में खामियाँ उजागर कीं 11

नोट :

दृष्टि The Vision

मध्य प्रदेश

‘एग्जाम पेपर लीक’ को रोकने हेतु कानून

चर्चा में क्यों ?

मध्य प्रदेश सरकार ‘एग्जाम पेपर लीक’ रोकने के लिये सख्त कानून बनाएगी।

मुख्य बिंदु:

- परीक्षा केंद्रों के प्रभारी सहित कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल है, को दंड देने हेतु सख्त कानून बनाया जाएगा।
  - कोई भी छात्र-छात्राओं को प्रश्न-पत्र उपलब्ध नहीं करा सकेगा।
- अगर सरकारी सिस्टम में कोई दिक्कत है तो वह भी इस कानून के दायरे में आएगा। ऐसे कृत्य आपराधिक गतिविधि के दायरे में आएंगे।
- इस कानून के साथ, MP स्कूल शिक्षा विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि छात्र "तनाव-मुक्त" माहौल में परीक्षा दें।

रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तथा पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने रीवा में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के विस्तार के लिये 164 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी है।

मुख्य बिंदु:

- इस निर्णय से रीवा और शहडोल संभाग के लोगों को लाभ होगा क्योंकि यह उन संभागों का सबसे बड़ा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल है।
- मंत्रिपरिषद ने राज्य में स्टार्टअप नीति को लेकर भी महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया।
  - सभी स्टार्टअप लोग जो राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये 50,000 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिये 1.50 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।
  - किसी स्टार्टअप के लिये यह राशि एक वित्तीय वर्ष में एक बार और पूरे कार्यकाल में दो बार तक दी जाएगी।
- करीब दो दशक से लंबित पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना अब पीएम की पहल से क्रियान्वित होगी।
  - इससे राज्य के मालवा और चंबल क्षेत्र के 12 ज़िलों तथा पूर्वी राजस्थान के 13 ज़िलों को लाभ होगा।
  - इन क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी तथा सिंचाई एवं औद्योगिक उपयोग के लिये भी जल उपलब्ध होगा।
  - यह परियोजना 75,000 करोड़ रुपए की है और इसमें राज्य केवल 10% निवेश करेंगें, बाकी 90% राशि केंद्र सरकार प्रदान करेगी।

पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना

- इसका उद्देश्य दक्षिणी राजस्थान में चंबल, कुन्नू, पार्वती, कालीसिंध सहित इसकी सहायक नदियों में बरसात के मौसम में उपलब्ध अतिरिक्त जल का संचयन करना और इस जल का उपयोग राज्य के दक्षिण-पूर्वी ज़िलों में करना है, जहाँ पीने तथा सिंचाई के लिये जल की कमी है।
- इस परियोजना का उद्देश्य वर्ष 2051 तक दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में मानव तथा पशुधन हेतु पीने के जल तथा औद्योगिक गतिविधियों हेतु जल की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना है।
- इसमें राजस्थान के 13 ज़िलों को पीने का जल उपलब्ध कराने और 26 विभिन्न बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं के माध्यम से 2.8 लाख हेक्टेयर भूमि के लिये सिंचाई का जल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
- 13 ज़िले: इसमें झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, जयपुर, करौली, अलवर, भरतपुर, दौसा और धौलपुर शामिल है।

पीएम ने मध्य प्रदेश में परियोजनाओं का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले में 7,500 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी और आदिवासी समुदायों के एक सम्मेलन को संबोधित किया।

मुख्य बिंदु:

- कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने:
  - राज्य की आहार अनुदान योजना के तहत लगभग दो लाख महिला लाभार्थियों को मासिक किश्तों का वितरण किया गया।
    - योजना के तहत, विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों की महिलाओं को पौष्टिक भोजन के लिये 1,500 रुपए प्रति माह प्रदान किये जाते हैं।
  - स्वामित्व (SVAMITVA) योजना के तहत 1.75 लाख 'अधिकार अभिलेख' (भूमि अधिकारों का रिकॉर्ड) वितरित किये गए, जो लोगों को उनकी भूमि के अधिकार हेतु दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रदान करेगा।
  - प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 559 गाँवों को 55.9 करोड़ रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई, जिसका उपयोग आंगनवाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकानों, स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों में अतिरिक्त कमरे, आंतरिक सड़कों सहित विभिन्न प्रकार की निर्माण गतिविधियों के लिये किया जाएगा।
- शिलान्यास:
  - टंट्या मामा भील विश्वविद्यालय जो राज्य के आदिवासी बहुल ज़िलों के युवाओं को शिक्षा प्रदान करेगा।
  - झाबुआ में 'सीएम राइज स्कूल' जो छात्रों को स्मार्ट क्लास, ई-लाइब्रेरी जैसी आधुनिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिये प्रौद्योगिकी को एकीकृत करेगा।
  - 'तलावड़ा परियोजना', जो धार एवं रतलाम के एक हजार से अधिक गाँवों के लिये पेयजल आपूर्ति योजना है तथा कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (AMRUT) 2.0 के तहत 14 शहरी जल आपूर्ति योजनाएँ, जिससे मध्य प्रदेश के कई ज़िलों में 50,000 से अधिक शहरी परिवार लाभान्वित हो रहे हैं।
  - झाबुआ की 50 ग्राम पंचायतों के लिये 'नल जल योजना', जिससे लगभग 11,000 घरों को नल का जल मिलेगा।
  - राष्ट्र को समर्पित की जाने वाली रेल परियोजनाओं में इंदौर-देवास-उज्जैन सी केबिन रेलवे लाइन के दोहरीकरण, यार्ड रिमॉडलिंग के साथ इटारसी-उत्तर-दक्षिण ग्रेड सेपरेटर और बरखेड़ा-बुदनी-इटारसी को जोड़ने वाली तीसरी लाइन की परियोजनाएँ शामिल हैं।
  - प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 3,275 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई सड़क विकास परियोजनाएँ भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।

अमृत 2.0

- अमृत मिशन को हर घर में जल की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ सभी की नल तक पहुँच को सुनिश्चित करने के लिये जून 2015 में शुरू किया गया था।
- अमृत 2.0 का लक्ष्य लगभग 4,700 ULB (शहरी स्थानीय निकाय) में सभी घरों में जल की आपूर्ति के मामले में 100% कवरेज प्रदान करना है।
- इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) को प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY)

- इसे वर्ष 2009-10 के दौरान लॉन्च किया गया था। इस योजना का लक्ष्य अनुसूचित जाति बहुल गाँवों का एकीकृत विकास करना है।
- इस योजना का उद्देश्य 50% से अधिक अनुसूचित जाति आबादी वाले चयनित गाँवों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है:
  - मुख्य रूप से प्रासंगिक केंद्र और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार की योजनाओं के अभिसरण कार्यान्वयन के माध्यम से और
  - प्रति गाँव 20,00,000 रुपय की सीमा तक केंद्रीय सहायता के रूप में प्रदान की गई 'गैप-फिलिंग' निधि के माध्यम से ऐसी चिन्हित गतिविधियों को शुरू करना जो मौजूदा केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत शामिल नहीं हैं।

नोट :

सिंगरौली में हल्का भूकंप आया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के सिंगरौली इलाके में हल्का भूकंप आया था।

- सिंगरौली अपनी कोयला खदानों और विद्युत संयंत्रों के लिये जाना जाता है।

मुख्य बिंदु:

- नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह से 5 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है।
  - परिमाण: 3.5
  - अक्षांश: 24.55
  - देशांतर: 82.78
- भूकंप: सरल शब्दों में कहें तो भूकंप पृथ्वी का हिलना है। यह एक प्राकृतिक घटना है। यह ऊर्जा की रिहाई के कारण होता है, जो सभी दिशाओं में यात्रा करने वाली तरंगें उत्पन्न करती है।
- अधिकेंद्र: सतह पर केंद्र के निकटतम बिंदु को अधिकेंद्र कहा जाता है। यह तरंगों का सबसे पहले अनुभव करता है। यह केंद्र के ठीक ऊपर एक बिंदु है।
- केंद्र: वह बिंदु जहाँ ऊर्जा जारी होती है उसे भूकंप का केंद्र कहा जाता है, वैकल्पिक रूप से, इसे हाइपोसेंटर कहा जाता है। इसमें विभिन्न दिशाओं में यात्रा करने वाली ऊर्जा तरंगें सतह तक पहुँचती हैं।
- राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS): यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत कार्य करता है। यह देश में भूकंप गतिविधि की निगरानी के लिये भारत सरकार की नोडल एजेंसी है।

नोट :

मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश ने पहला राज्य बजट पेश किया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिये लगभग 1 लाख 45 हज़ार करोड़ रुपए का अंतरिम बजट (लेखानुदान) पेश किया।

मुख्य बिंदु:

- सीएम मोहन यादव का पहला अंतरिम बजट केवल चार महीने (1 अप्रैल से 31 जुलाई, 2024) के लिये विभिन्न योजनाओं में अपने व्यय का प्रबंधन करने के लिये है।
    - अंतरिम बजट में आवंटित राशि को जुलाई 2024 में पेश किये जाने वाले पूर्ण बजट में मिला दिया जाएगा।
- वित्त वर्ष 2024-25 के लिये राज्य का वित्तीय बजट (पूर्ण बजट) लगभग 3 लाख 48 हज़ार 986 करोड़ अनुमानित है।
- चार महीने के लिये अंतरिम बजट केवल व्यय पर केंद्रित होता है तथा बजट में कोई नई वस्तु या नए प्रस्ताव नहीं होते हैं।

लेखानुदान

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार, लेखानुदान केंद्र सरकार के लिये अग्रिम अनुदान के रूप में है, इसे भारत की संचित निधि से अल्पकालिक व्यय की आवश्यकता को पूरा करने के लिये प्रदान किया जाता है और आमतौर पर नए वित्तीय वर्ष के कुछ शुरुआती महीनों के लिये जारी किया जाता है।
    - एक चुनावी वर्ष के दौरान सरकार या तो अंतरिम बजट 'या 'लेखानुदान' को ही जारी करती है क्योंकि चुनाव के बाद नई सरकार पुरानी सरकार की नीतियों को बदल सकती है।
    - किसी विनियोग विधेयक की राशि में परिवर्तन करने या अनुदान के लक्ष्य को बदलने अथवा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की राशि में परिवर्तन करने का प्रभाव रखने वाला कोई संशोधन, संसद के सदन में प्रख्यापित नहीं किया जा सकता है और ऐसे संशोधन की स्वीकार्यता के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।
    - यह नियमित बजट स्वीकृत होने तक सरकार और सार्वजनिक सेवाओं के सुचारु कामकाज को सुनिश्चित करता है।

भारत की संचित निधि

- इसकी स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के तहत की गई थी।
- इसमें समाहित हैं:
    - करों के माध्यम से केंद्र को प्राप्त सभी राजस्व (आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और अन्य प्राप्तियाँ) तथा सभी गैर-कर राजस्व।
    - सार्वजनिक अधिसूचना, ट्रेज़री बिल (आंतरिक ऋण) और विदेशी सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों (बाहरी ऋण) के माध्यम से केंद्र द्वारा लिये गए सभी ऋण।
- सभी सरकारी व्यय इसी निधि से पूरे किये जाते हैं (असाधारण मदों को छोड़कर जो लोक लेखा निधि या सार्वजनिक निधि से संबंधित हैं) और संसद के प्राधिकरण के बिना निधि से कोई राशि नहीं निकाली जा सकती।
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) इस निधि का लेखा परीक्षण करते हैं।

खजुराहो नृत्य महोत्सव के 50 वर्ष पूरे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खजुराहो नृत्य महोत्सव की स्वर्ण जयंती (50वें संस्करण) कार्यक्रम का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर 1484 कलाकारों ने सबसे अधिक संख्या में कलाकारों के साथ सबसे बड़े कथक नृत्य प्रदर्शन का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया।

नोट :

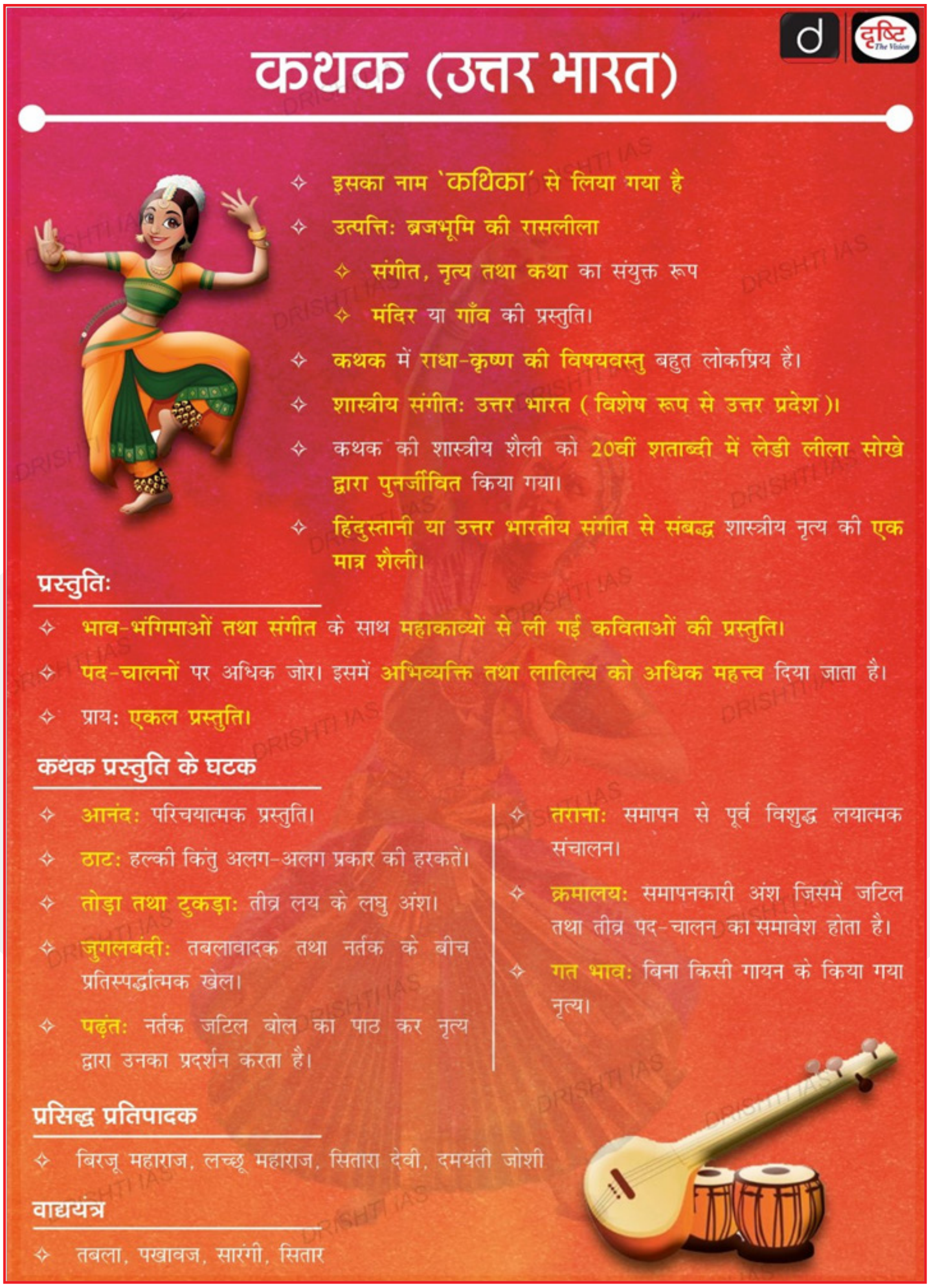

मुख्य बिंदु:

- प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल पर 'कथक कुंभ' का रिकॉर्ड स्थापित करने वाला (विश्व रिकॉर्ड) प्रदर्शन उज्जैन तथा ग्वालियर आयोजनों के बाद लगातार तीसरा प्रदर्शन है, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा भी दर्ज और मान्यता दी गई है।
  - उज्जैन में 11 लाख 71 हज़ार 78 दीये जलाये गए।
  - जबकि ग्वालियर के तानसेन समारोह में ग्वालियर किले में ताल दरबार के दौरान कुल 1600 की संख्या में तबला कलाकारों ने एक साथ ताल बजाई।
- सीएम ने खजुराहो में आदिवासी और लोक कलाओं के प्रशिक्षण के लिये देश का पहला गुरुकुल स्थापित करने की घोषणा की।

नोट :

- खजुराहो नृत्य महोत्सव (KDF) का आयोजन प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला के मार्गदर्शन में सांस्कृतिक एवं पर्यटन विभाग द्वारा किया जा रहा है।
- KDF ने इस कार्यक्रम को भगवान नटराज महादेव को समर्पित करने का फैसला किया है, जिन्हें अक्सर 'नृत्य के देवता' के रूप में जाना जाता है। यह विशेष शिव अवतार दर्शाता है कि कैसे नृत्य भगवान के साथ सीधे संपर्क का एक पवित्र माध्यम है।
- प्रसिद्ध नृत्य गुरु राजेंद्र गंगानी की कोरियोग्राफी में प्रदेश के विभिन्न शहरों से आए कलाकारों ने राग बसंत में मनमोहक प्रस्तुति दी।
- गुरुकुल में वरिष्ठ विशेषज्ञों और 'गुरुओं' की सहायता से विशेष शिल्प, नेतृत्व, गायन, संगीत, चित्रकला, क्षेत्रीय साहित्य सिखाने के पाठ्यक्रमों के साथ आदिवासी तथा ग्रामीण समुदायों की पारंपरिक कलाओं में प्रशिक्षण के इच्छुक उम्मीदवारों के लिये सभी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

खजुराहो नृत्य महोत्सव

- खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत वर्ष 1975 में की गई थी और तब से आज तक मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग के अंतर्गत उस्ताद अलाउद्दीन खाँ संगीत एवं कला अकादमी द्वारा इसका सफल आयोजन निरंतर किया जाता रहा है। तब से लेकर आज तक यह नृत्य समारोह खजुराहो के सुप्रसिद्ध मंदिरों के प्रांगण में आयोजित होता आ रहा है।
- खजुराहो नृत्य महोत्सव में अब तक भारत की सभी प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों जैसे भरतनाट्यम, ओडीसी, कथक, मोहिनीअटेम, कुचिपुड़ी, कथकली, यक्षगान, मणिपुरी आदि के युवा और वरिष्ठ कलाकार अपनी कला की आभा बिखेर चुके हैं।
- महोत्सव के माध्यम से नृत्य में शास्त्रीयता की गरिमा बनाए रखने के साथ नवाचार करने का प्रयास किया जाता रहा है।

मध्य प्रदेश ने 'बैग लेस स्कूल' पहल शुरू की

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिये सप्ताह में एक बार 'बैग लेस स्कूल' दिवस की घोषणा की है। यह निर्णय राज्य में संचालित सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होता है।

मुख्य बिंदु:

- राज्य सरकार ने छात्रों पर बोझ कम करने के उद्देश्य से विभिन्न कक्षाओं के लिये स्कूल बैग के अधिकतम स्वीकार्य वज़न की रूपरेखा बताते हुए एक नोटिस जारी किया है।
- कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिये स्कूल बैग का वज़न स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा छात्रों की संबंधित स्ट्रीम के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
- इस पहल में प्रत्येक सप्ताह एक निर्दिष्ट 'बैग लेस स्कूल' दिवस शामिल है, जिसके दौरान छात्रों को खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत जैसी मनोरंजक गतिविधियों में शामिल होने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।
- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल को छात्रों के लिये तनाव का स्रोत नहीं बल्कि आनंद का स्रोत माना जाए।
  - स्कूलों को वर्ष 2024-25 में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से नई स्कूल बैग नीति का पालन करने के सख्त निर्देश जारी किये गए हैं।

मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड को 'सर्वश्रेष्ठ राज्य पर्यटन बोर्ड' का पुरस्कार मिला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने में उत्कृष्ट नवाचारों के लिये मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड (MPTB) को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया।

मुख्य बिंदु:

- ग्रेटर नोएडा में आयोजित देश की प्रमुख यात्रा प्रदर्शनी SATTE (साउथ एशियन ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्सचेंज) में MPTB को 'बेस्ट टूरिज्म स्टेट बोर्ड' का पुरस्कार दिया गया है।

नोट :

- बोर्ड ने तीन दिवसीय प्रदर्शनी में प्रमुखता से भाग लिया और देश-विदेश के ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों, होटल व्यवसायियों एवं विभिन्न हितधारकों के समक्ष राज्य के पर्यटन स्थलों व उत्पादों का प्रचार-प्रसार किया।
- बोर्ड को यह सम्मान पर्यटन, बुनियादी ढाँचे के विकास, स्थानीय समुदाय के आर्थिक विकास, राज्य की संस्कृति और विरासत के संरक्षण के क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रदर्शन के आधार पर दिया गया है।

नोट:

- कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थल:
  - भोपाल- गोहर महल, झीलें, बिड़ला मंदिर, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, आदि।
  - भेड़ाघाट- चौंसठ योगिनी मंदिर, धुआँधार झरना, संगमरमर की चट्टान।
  - जबलपुर- मदन महल, कचनार सिटी शिव मंदिर, डुमना नेचर पार्क।
  - तामिया- झरने, पेंच टाइगर रिजर्व
  - पचमढ़ी- सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, छोटा महादेव, धूपगढ़।
- मध्य प्रदेश के कुछ एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP):
  - श्योपुर- गुवा
  - ग्वालियर- बलुआ पत्थर की टाइलें
  - दतिया- गुड़
  - पन्ना- करौंदा/आँवला
  - उज्जैन- बाटिक प्रिंट
  - भोपाल- ज़री ज़रदोज़ी और जूट उत्पाद
  - रायसेन- बासमती चावल
  - सिवनी- सीताफल

प्रधानमंत्री ने रेलवे परियोजनाओं का अनावरण किया

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3,276 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं की घोषणा की, जिसमें मध्य प्रदेश के लिये 33 स्टेशनों का नवीनीकरण भी शामिल है।

मुख्य बिंदु:

- पुनर्विकास के लिये चिह्नित स्टेशनों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सीहोर, बीना, सांची, मंदसौर, छिंदवाड़ा, दतिया और भिंड शामिल हैं।
- अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों को स्थानीय कला और संस्कृति के तत्त्वों से सजाया जाएगा।
  - 492 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में इंदौर रेलवे स्टेशन को सात मंज़िला इमारत में तब्दील किया जाएगा। पुनर्निर्मित स्टेशन वर्ष 2027 तक चालू हो जाएगा।
  - आवंटित राशि से 33 स्टेशनों पर पुनर्विकास कार्य होगा, जिसमें भोपाल मंडल के 11 स्टेशन शामिल हैं।
- 133 रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास किया जाएगा। इन कार्यों में पाँच स्टेशनों का पुनर्विकास और भोपाल मंडल में चार रोड ओवरब्रिज तथा दो अंडरपास का निर्माण शामिल होगा।

अमृत भारत स्टेशन योजना

- अमृत भारत स्टेशन योजना का लक्ष्य देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना है।

नोट :

- यह पुनर्विकास आधुनिक यात्री सुविधाएँ प्रदान करने के साथ-साथ इंटर-मोडल एकीकरण तथा यात्रियों के लिये सुव्यवस्थित दिशा-निर्देश की सुविधा प्रदान करने के लिये साइनेज़ (संकेतों के माध्यम से) सुविधा भी सुनिश्चित करेगा।
- यह योजना रेल मंत्रालय द्वारा फरवरी 2023 में शुरू की गई थी।

प्रधानमंत्री 'विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश' कार्यक्रम को संबोधित करेंगे

चर्चा में क्यों ?

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 फरवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए 'विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश' कार्यक्रम को संबोधित करेंगे।

मुख्य बिंदु:

- इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
  - इन परियोजनाएँ में सिंचाई, विद्युत, सड़क, रेल, जल आपूर्ति, कोयला, उद्योग सहित कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं।
  - प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में साइबर तहसील परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे।
- वह मध्य प्रदेश में 5500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सिंचाई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे।
  - इन परियोजनाओं में अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसनिया बहुउद्देशीय परियोजना शामिल हैं।
  - प्रधानमंत्री 800 करोड़ से अधिक की दो सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाएँ भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे जिनमें पारसडोह सूक्ष्म सिंचाई परियोजना और औलिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री 2200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित तीन रेलवे परियोजनाएँ भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे।
- इन परियोजनाओं में रतलाम में बड़ा औद्योगिक पार्क; मुरैना ज़िले के सीतापुर में मेगा चमड़ा, जूते एवं सहायक उपकरण केंद्र; इंदौर में परिधान उद्योग के लिये प्लग एंड प्ले पार्क; औद्योगिक पार्क मंदसौर (जग्गाखेड़ी चरण-2); और धार ज़िले में औद्योगिक पार्क पीथमपुर का उन्नयन परियोजना शामिल हैं।
- प्रधानमंत्री अमृत 2.0 के तहत लगभग 880 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं और राज्य भर के कई ज़िलों में जल आपूर्ति प्रणालियों को बढ़ाने तथा मज़बूत करने की अन्य योजनाओं की आधारशिला रखेंगे।

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (AMRUT 2.0)

- यह जून 2015 में शुरू किये गए अमृत मिशन की निरंतरता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ नल की पहुँच हो।
- अमृत 2.0 का लक्ष्य लगभग 4,700 ULB (शहरी स्थानीय निकाय) में सभी घरों में पानी की आपूर्ति के मामले में 100% कवरेज प्रदान करना है।
- इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स (सार्वजनिक-निजी भागीदारी) को प्रोत्साहित करके आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा देना है।

मध्य प्रदेश भगवान कृष्ण से जुड़े स्थलों का विकास करेगा

चर्चा में क्यों ?

'राम वन गमन पथ' को विकसित करने की योजना की घोषणा के बाद, मध्य प्रदेश सरकार राज्य में भगवान कृष्ण से जुड़े स्थानों को भी विकसित करेगी।

- माना जाता है कि 'राम वन गमन पथ' वह मार्ग है जिसे भगवान राम ने वन में वनवास के लिये जाते समय अपनाया था।

मुख्य बिंदुः

- मुख्यमंत्री ने पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों से कहा कि राज्य में भगवान श्रीकृष्ण के भ्रमण स्थलों पर तीर्थयात्रियों के लिये भी आवश्यक व्यवस्थाएँ की जाएँ।
  - भगवान कृष्ण मथुरा से उज्जैन राज्य में गए और ऋषि सांदीपनि के आश्रम में रहे जहाँ उन्होंने विभिन्न कलाएँ सीखीं तथा वेदों का अध्ययन किया।
  - धार ज़िले के अमझेरा स्थित नारायण धाम और उज्जैन ज़िले की महिदपुर तहसील का भी विशेष धार्मिक महत्त्व है।
  - अमझेरा में शैव और वैष्णव संप्रदाय के कई प्राचीन मंदिर हैं तथा यह भगवान कृष्ण एवं रुक्मणी से जुड़ा हुआ है।
  - नारायण धाम में विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ भगवान कृष्ण अपने मित्र सुदामा के साथ नज़र आते हैं।
- बेहतर सुविधाओं और बुनियादी ढाँचे से इन स्थानों पर पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं का प्रवाह बढ़ेगा।
- निकट भविष्य में आम लोगों को शामिल करके अंतर्राष्ट्रीय गीता और रामायण महोत्सव आयोजित किया जा सकता है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था की सहायता के लिये देवी-देवताओं की लघु मूर्तियों के निर्माण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

CAG ने मध्य प्रदेश पीएम आवास योजना में खामियाँ उजागर कीं

चर्चा में क्यों ?

भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G) के कार्यान्वयन में अनियमितताओं को चिह्नित किया है।

मुख्य बिंदुः

- सार्वजनिक आवास कार्यक्रम को केंद्र द्वारा वर्ष 2016 में गरीबी उन्मूलन के एक साधन के रूप में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे और जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध कराना था।
  - अंतरिम बजट 2024 में वित्त मंत्रालय ने PMAY-G के तहत अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण की घोषणा की।
- CAG की रिपोर्ट में वर्ष 2016-21 से इस योजना के कार्यान्वयन की बात की गई है, जब 26,28,525 घरों को मंज़ूरी दी गई थी और 24,723 करोड़ रुपए लाभार्थियों को दिये गए थे।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि:
  - स्वीकृत आवासों में से 82.35% पूर्ण हो चुके हैं।
  - हालाँकि इस योजना में यह अनिवार्य है कि वाहन या मछली पकड़ने वाली नाव वाले परिवारों को बाहर रखा जाए, 10 लेखापरीक्षित ज़िलों में घर की मंज़ूरी से पहले 2,037 लाभार्थियों के पास दो/तीन/चार पहिया वाहन थे।
  - 2,037 अयोग्य लाभार्थियों में से 1,555 को 15.66 करोड़ रुपए की PMAY-G सहायता।
  - 64 मामलों में एक ही लाभार्थी को दो बार आवास स्वीकृत किये गए। 98 मामलों में, एक घर वास्तविक लाभार्थी को और दूसरा उसके परिवार के सदस्यों को स्वीकृत किया गया था, जिनकी योजना के लिये पहचान नहीं की गई थी।
  - लाभार्थियों के डुप्लिकेट की पहचान करने के लिये पोर्टल में अलर्ट करने की कोई व्यवस्था नहीं है।
  - कुल 18,935 स्वीकृत मामलों में से 8,226 लाभार्थियों ने प्राथमिकता सूची में अधिक वंचित लाभार्थियों को हटा दिया।
  - रिपोर्ट में लाभार्थियों को किश्तें देने में देरी भी देखी गई, जिसके कारण घर बनाने में देरी हुई।
  - 90 मामलों में नाबालिगों को PMAY-G आवास स्वीकृत किया गया और उनके रिश्तेदारों को लाभ प्रदान किया गया।
  - आवास सॉफ्ट डेटा की जाँच की गई क्योंकि 1,246 मामलों में लाभार्थियों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था और 950 मामलों में लाभ जारी किया गया था।
    - आवास सॉफ्ट, एक वेब-आधारित लेन-देन संबंधी इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण मंच है, जिसका उपयोग योजना के कार्यान्वयन और निगरानी में किया जाता है।

नोट :

- योजना की रूपरेखा यह निर्धारित करती है कि "विधवा/अविवाहित/अलग हुए व्यक्ति के मामले को छोड़कर घर का आवंटन पति और पत्नी के नाम पर संयुक्त रूप से किया जाएगा" का भी उल्लंघन किया गया था।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G)

- इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 तक 'सभी के लिये आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु शुरू किया गया था। ज्ञात हो कि पूर्ववर्ती 'इंदिरा आवास योजना' (IAY) को 01 अप्रैल, 2016 को 'प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण' के रूप में पुनर्गठित किया गया था।
- इसमें शामिल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय है।
- जीवन व्यतीत कर रहे ग्रामीण परिवारों को आवासीय इकाइयों के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों के उन्नयन में गरीबी रेखा (BPL) से नीचे वाले लोगों की पूर्ण अनुदान के रूप में सहायता प्रदान करना।
- लाभार्थियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोग, मुक्त बंधुआ मज़दूर और गैर-एससी/एसटी वर्ग, विधवा महिलाएँ, रक्षाकर्मियों के परिजन, पूर्व सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सदस्य, विकलांग व्यक्ति एवं अल्पसंख्यक शामिल हैं।
- यूनिट सहायता की लागत को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मैदानी क्षेत्रों में 60:40 के अनुपात में तथा उत्तर-पूर्वी एवं पहाड़ी राज्यों के लिये 90:10 के अनुपात में साझा किया जाता है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

- अनुच्छेद 148 CAG के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। यह भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था है।
  - CAG से संबंधित अन्य प्रावधानों में अनुच्छेद 149-151 (कर्त्तव्य और शक्तियाँ, संघ व राज्यों के खातों का स्वरूप तथा अंकेक्षण रिपोर्ट), अनुच्छेद 279 (निवल आय का परिकलन इत्यादि) तथा तीसरी अनुसूची (शपथ अथवा प्रतिज्ञान) एवं छठी अनुसूची (असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिज़ोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन) शामिल हैं।
- जनता के धन का संरक्षक और केंद्र एवं राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है।
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, के लिये नियुक्त किया जाता है।
- CAG को राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर, या तो साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है।

✦ ✦ ✦ ✦